vinetur

फ्रांस का लेखा न्यायालय 2027 में रेस्तरां पर वैट दोगुना कर 20% करने के पक्ष में

बजट रिपोर्ट के अनुमान के अनुसार, विधायकों की मंजूरी मिलने पर व्यापक राजकोषीय योजना के तहत इस बदलाव से €4.6 billion जुटाए जा सकते हैं

मंगलवार, 10 नवंबर 2026



फ्रांस के लेखा न्यायालय ने 2027 में रेस्तरां सेवाओं पर मूल्यवर्धित कर (वैट) बढ़ाकर 20% करने का प्रस्ताव रखा है। इसे मंजूरी मिलने पर क्षेत्र के लिए मौजूदा 10% की दर दोगुनी हो जाएगी और आतिथ्य उद्योग में मेनू की कीमतों, परिचालन मार्जिन तथा उपभोक्ता मांग पर सीधा असर पड़ सकता है।

यह प्रस्ताव सोमवार, 9 नवंबर को प्रकाशित बजट रिपोर्ट में सामने आया। रिपोर्ट में न्यायालय ने फ्रांस की सार्वजनिक वित्तीय स्थिति सुधारने में मदद के लिए अल्पकालिक और मध्यम अवधि के कई उपाय पेश किए। न्यायालय के मुताबिक, 2027 के लिए एक विकल्प रेस्तरां सेवाओं और कुछ अन्य गतिविधियों को कम 10% वैट दर से हटाकर मानक 20% दर के दायरे में लाना है। उसने एक अन्य विकल्प भी पेश किया : सामान्य मध्यवर्ती वैट दर को बढ़ाकर 13% करना। न्यायालय ने कहा कि इन दोनों विकल्पों से क्रमशः अनुमानित €4.6 billion और €4.3 billion का राजस्व मिलेगा।

न्यायालय ने किसी कानूनी बदलाव की घोषणा नहीं की है और यह प्रस्ताव अपने आप लागू नहीं होगा। वैट बढ़ाने के लिए फ्रांस की सरकार और संसद को विधायी कार्रवाई करनी होगी। न्यायालय ने खुद कहा कि उसका काम सार्वजनिक बहस को जानकारी देना और नीति-निर्माताओं के सामने प्रमाण-आधारित विकल्प रखना है, न कि निर्णय थोपना।

रेस्तरां के लिए यह प्रस्ताव अहम है, क्योंकि वैट अंतिम कीमतों और नकदी प्रवाह का सीधा हिस्सा होता है। 10% से 20% की बढ़ोतरी उस क्षेत्र को प्रभावित करेगी, जहां वर्षों से मानक दर से कम वैट लागू है। कारोबारियों को तय करना होगा कि वे बढ़े हुए कर का बोझ ग्राहकों पर डालें, पहले से ही दबाव में चल रहे मार्जिन से उसका कुछ हिस्सा खुद वहन करें या कर्मचारियों, निवेश अथवा अन्य लागतों में बदलाव करें। रिपोर्ट यह नहीं बताती कि अलग-अलग कारोबारी किस तरह प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन स्पष्ट करती है कि 2027 के लिए राजस्व जुटाने के उपाय के तौर पर इस प्रस्ताव पर विचार हो रहा है।

वैट का प्रस्ताव एक व्यापक पैकेज का हिस्सा है। 9 नवंबर की रिपोर्ट में लेखा न्यायालय ने कहा कि उसने अपने काम और Council on Mandatory Levies से 18 ऐसे उपायों को संकलित किया है, जिनका असर 2027 से दिखना शुरू हो सकता है। न्यायालय ने इस पैकेज से संभावित राजस्व €32 billion से €38 billion के बीच आंका। उसने कहा कि इन उपायों का चयन दो सिद्धांतों के आधार पर किया गया : सार्वजनिक खर्च में राज्य, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली और स्थानीय प्राधिकरणों की हिस्सेदारी के लगभग अनुपात में समायोजन का बोझ बांटना, और खर्च में कटौती को प्राथमिकता देना।

यह रिपोर्ट फ्रांस की राजकोषीय स्थिति को लेकर न्यायालय की पिछली चेतावनियों के बाद आई है। न्यायालय ने कहा कि आर्थिक परिदृश्य बिगड़ने से सार्वजनिक वित्त को दुरुस्त करने की जरूरत और अधिक तत्काल हो गई है। उसने यह भी कहा कि उसके पैकेज के कुछ उपाय 2027 के मसौदा वित्त विधेयकों में पहले से पेश प्रावधानों से मेल खाते हैं। इनका अनुमानित मूल्य €11 billion से €14 billion के बीच है, हालांकि अंतिम राजस्व इस बात पर निर्भर करेगा कि विधेयकों का कौन-सा स्वरूप अंततः पारित होता है।

अल्पकालिक प्रस्तावों के साथ-साथ न्यायालय ने 13 दीर्घकालिक उपाय भी पेश किए, जिन्हें भविष्य के बहुवर्षीय सार्वजनिक वित्त कानून में शामिल किया जा सकता है। इन सुझावों का जोर मध्यम अवधि की बजट योजना मजबूत करने, सरकार के विभिन्न स्तरों पर सार्वजनिक खर्च पर कड़ा नियंत्रण रखने और सार्वजनिक प्रशासन के बीच वित्तीय समन्वय बेहतर बनाने पर है।

रिपोर्ट के साथ प्रकाशित एक अलग टिप्पणी में कर रियायतों पर ध्यान दिया गया, जिन्हें न्यायालय ने सार्वजनिक वित्त पर बढ़ते दबाव का स्रोत बताया। उसके अनुसार, कर रियायतों की लागत 20 वर्षों में लगभग दोगुनी हो गई : स्थिर दायरे और मौजूदा यूरो के आधार पर यह 2005 में €54.6 billion से बढ़कर 2025 में €105.6 billion हो गई। न्यायालय के मुताबिक, 2025 में फ्रांस में इस तरह के 474 कर उपाय थे और अब इनका हिस्सा राज्य के कर राजस्व के एक-चौथाई से अधिक है।

न्यायालय ने कहा कि ये आंकड़े कर रियायतों पर कड़ा नियंत्रण रखने की जरूरत दिखाते हैं। इसके तहत उनकी अवधि और लागत सीमित करना तथा उनकी प्रभावशीलता का नियमित मूल्यांकन करना शामिल है। यह व्यापक तर्क रेस्तरां वैट प्रस्ताव के लिए भी प्रासंगिक है, क्योंकि अतिरिक्त राजस्व जुटाने के उपायों की तलाश में कम दर वाले वैट की भी पड़ताल की जा रही है।

रेस्तरां वैट को 2027 के विकल्पों में शामिल करके लेखा न्यायालय ने इस क्षेत्र को फ्रांस की बजट बहस के केंद्र में ला दिया है। यह उपाय अभी प्रस्ताव मात्र है, लेकिन इससे रेस्तरां और आतिथ्य क्षेत्र के कारोबारियों को संकेत मिलता है कि सार्वजनिक वित्त को दुरुस्त करने की सरकार की व्यापक कोशिश के तहत बड़े कर-वृद्धि पर विचार किया जा रहा है।